(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह अनुमति कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) मानखुर्द-बैलापुर रेल परियोजना की वित्त-व्यवस्था हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान बाजार ऋण के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की रकम जुटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Settlement Commission for Income Tax/ Wealth Tax

3667. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Settlement Commission for Income Tax and Wealth Tax is considered to be a quasi judicial body;

(b) if so, what is its composition;

(c) the details of the mode of recruitment of these posts; and

(d) whether Judicial Officers are also given representation on this Commission; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHARA MURTHY): (a) Yes.

(b) The Income-tax Settlement Commission has a Principal Bench at Delhi and three Additional Benches at Bombay, Calcutta and Madras. The Chairman presides over the Principal Bench and the Additional Benches are presided over by Vice-Chairman. Each Bench has in addition two posts of Member.

(c) and (d). Appointments of Chairman, Vice-Chairman and Members of the Commission are made in accordance with the provisions of Section 245B (3) of the Income-tax Act which require persons having special knowledge of, and experience in, problems relating to direct taxes and business accounts to be considered for the same. Since only the officers of Indian Revenue Service possess this knowledge and experience, officers belonging to other disciplines are not being considered.

Effect of GATT on Indian Economy

3668. SHRI K. R. MALKANI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Hon'ble Finance Minister has said that GATT will benefit the country in the long run as reported in Hindu of 1st August, 1994; and

(b) what will be the long-term benefits, and short term losses to Indian economy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) The Finance Minister while addressing a seminar on GATT organised by the National Economic Development Forum in Madras on Sunday the 31st July, 1994 outlined some of the benefits in terms of market access and new export markets accruing from India's signature of the Final Act of the Uruguay Round in the context of appraising its results.

(b) The Uruguay Round results will establish a rule-based multilateral trading system with expanded coverage. This will on the whole be advantageous to us in increasing our exports. There will be increased market access opportunities for Indian goods as a result of lowering of tariff and the phase out of the Multi Fibre Arrangement. The services Agreement would also provide export opportunities. The rules governing the multilateral trading system have been strengthened. Though we will be required to amend our patents regime, there are safeguards in the agreement against the abuse of patent rights by the right holder. The use of price control measures is also not prohibited. We have flexibility to devise our sui generis system of plant variety protection with provisions for farmers and researchers rights. In the area of agriculture, our development and public welfare policies will not be constrained.

अनिवासी भारतीयों को ऋण सुविधाएं

3669. चौधरी हरमोहन सिंह:
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरौला:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन अनिवासी भारतीयों को ऋण सुविधाएं प्रदान करती है जो देश में पूंजी-निवेश करते हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनिवासी भारतीयों को अब तक प्रदान की गई ऋण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्राधिकृत डीलरों को अनिवासी भारतीयों के लिए निवेश उद्देश्यों हेतु उनके द्वारा बैंकों में जमा राशि की जमानत पर कतिपय शर्तों के अन्तर्गत अन्य उद्देश्यों के लिए और भारत में अपने आवासीय उपयोग हेतु घर/फ्लैट का अधिग्रहण करने के लिए ऋण प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। प्राधिकृत डीलरों को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी अनिवासी भारतीयों के बाण्डों के विरुद्ध ऋण प्रदान करें। उपर्युक्त के अलावा, अनिवासी भारतीय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत संस्थाओं से गृह निर्माण ऋण की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं

विदेशी मुद्रा की कमी के कारण विकास दर में गिरावट

3670. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी ऋण के भुगतान और विदेशी मुद्रा की कमी के परिणामस्वरूप देश की विकास दर में गिरावट आने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान अनुमानित व्यापार घाटा कितना रहा है और देश पर कितना घरेलू और विदेशी ऋण बकाया है तथा इस पर कितनी धनराशि का ब्याज देय है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान व्यापार-घाटा, जिसका वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा अनन्तिम रूप से अनुमान लगाया था, 1039 मिलियन डालर (3259 करोड़ रुपए) था। संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार 1993-94 के अन्त तक केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण और अन्य देयताएं 425,727 करोड़ रुपए रहीं और 1993-94 के दौरान ऋण पर देय ब्याज 33,625 करोड़ रुपए रहा। मार्च, 1994 के अन्त तक राष्ट्र के प्रति कुल बाह्य ऋण का स्टाक 90.7 बिलियन डालर (284,081 करोड रुपए) होने का अनुमान लगाया गया है। 1993-94 के दौरान राष्ट्र द्वारा बाह्य ऋण पर 3.6 बिलियन डालर (11,314 करोड़ रुपए) ब्याज भुगतान किए जाने का अनुमान है।

बिहार में विदेशी सहायता से शुरू की गई परियोजनायें

3671. **श्री आस मोहम्मद:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य में विदेशी सहायता से इस समय कौन-कौन सी परियोजनायें शुरू की जा रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के लिये किस प्रकार की सहायता दी गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा दी जाने वाली सहायता

3672. **श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई॰ एफ॰ ए॰ डी॰) को गुजरात में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक परियोजना शुरू करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को लाभ मिलेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गुजरात में कराया गया सर्वेक्षण

3673. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक